



Daily करेंट अफेयर्स

➤ 30 अगस्त 2025



NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क और BioE3 चैलेंज लॉन्च किया।



केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 27 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में युवाओं के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार हेतु जैव प्रौद्योगिकी (BioE3) चैलेंज का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को मज़बूत करना है।

- भारत का पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क, बायोई3 नीति के तहत एक रणनीतिक पहल है, जो इसके अपनाए जाने के एक वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यह शुभारंभ स्वास्थ्य सेवा से लेकर कृषि तक, विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के विस्तार के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क में छह प्रमुख संस्थान शामिल हैं: इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (ICGEB), बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल-नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (BRIC-NABI), ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI), इंस्टीट्यूट ऑफ

पेस्टिसाइड फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (IPFT), नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस (NCCS), और टाटा मेमोरियल सेंटर का एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (एक्ट्रेक)।

Key Points:-

(i) युवाओं के लिए BioE3 चैलेंज भी "डिज़ाइन माइक्रोब्स, मॉलिक्यूल्स और अन्य" थीम के साथ शुरू किया गया। यह चैलेंज स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12), स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। प्रतिभागियों को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने वाले सुरक्षित डिज़ाइन वाले जैव-समाधान तैयार करने का काम सौंपा गया है।

(ii) BioE3 चैलेंज अक्टूबर 2025 से शुरू होकर सालाना आयोजित किया जाएगा। हर महीने, शीर्ष 100 विजेताओं को प्रमुख जैव-नवाचार विशेषज्ञों से मान्यता और मार्गदर्शन के साथ 1.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। (ii) BioE3 चैलेंज अक्टूबर 2025 से शुरू होकर सालाना आयोजित किया जाएगा। हर महीने, शीर्ष 100 विजेताओं को प्रमुख जैव-नवाचार विशेषज्ञों से मान्यता और मार्गदर्शन के साथ 1.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, 100 सर्वश्रेष्ठ टीमों को आगे के समर्थन के लिए चुना जाएगा, जिन्हें जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के माध्यम से ₹25 लाख तक का वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। यह वित्त पोषण, प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट बायोटेक समाधानों के विकास और उन्हें स्केलेबल उत्पादों में बदलने में तेज़ी लाने में मदद करेगा।

2. कैबिनेट ने 27 अगस्त 2025 को PM SVANidhi योजना को 2030 तक बढ़ाने और अहमदाबाद में

2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली को मंजूरी दी।



27 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी आजीविका को बढ़ावा देने और खेलों में भारत की वैश्विक छवि को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये निर्णय अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमियों को सशक्त बनाने और खेल कूटनीति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

● कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दे दी है। मूल रूप से 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली इस योजना की ऋण अवधि को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इस संशोधित योजना में ₹7,332 करोड़ का वित्तीय परिव्यय शामिल है और इसमें स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण तक पहुँच में सुधार लाने और उनकी आर्थिक स्थिति को और मज़बूत करने के लिए एक नई क्रेडिट कार्ड सुविधा की शुरुआत भी शामिल है।

● केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए भारत की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिसमें अहमदाबाद को मेज़बानी शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस निर्णय में मेज़बानी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी देना और बोली सफल होने पर

गुजरात सरकार को वित्तीय सहायता (अनुदान सहायता) देने की प्रतिबद्धता शामिल है।

● अहमदाबाद को उसके विश्वस्तरीय स्टेडियमों, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और जोशीली खेल संस्कृति के कारण "आदर्श" स्थल चुना गया था। शहर का बुनियादी ढाँचा—जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम और हाल ही में 2023 ICC क्रिकेट विश्व कप फ़ाइनल की मेज़बानी शामिल है—इस तरह के वैश्विक खेल आयोजन के लिए इसकी उपयुक्तता को पुष्ट करता है।

Key Points:-

(i) घरेलू स्वीकृतियों के साथ-साथ, सरकार ने बाहरी आर्थिक दबावों का भी सामना किया—भारत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित 50% टैरिफ का विरोध करने का फैसला किया। यह कदम बढ़ते वैश्विक तनावों के बीच व्यापार कूटनीति पर एक व्यापक रणनीतिक रुख को दर्शाता है।

(ii) PM SVANidhi योजना का विस्तार, रेहड़ी-पटरी वालों के बीच आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है—जो भारत के अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है। अनुकूलित ऋण सुविधा प्रदान करके, यह योजना शहरी आजीविका को स्थिर और औपचारिक बनाने में मदद करती है।

(iii) राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की दावेदारी खेल कूटनीति के ज़रिए अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करती है। अगर यह आयोजन सफल रहा, तो इससे बुनियादी ढाँचे के उन्नयन, रोज़गार सृजन और खेल एवं पर्यटन के क्षेत्र में अहमदाबाद की वैश्विक छवि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. C-DOT ने अपनी स्थापना के 41 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में 42वां स्थापना दिवस मनाया।



संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) के अंतर्गत प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) ने 25 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में अपना 42वाँ स्थापना दिवस मनाया। 1984 में स्थापित, C-DOT ने भारत के दूरसंचार नवाचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- C-DOT के 42वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने किया। साथ ही, दूरसंचार विभाग के सचिव (दूरसंचार) डॉ. नीरज मित्तल भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में भारत की दूरसंचार प्रगति में सी-डॉट की विरासत पर प्रकाश डाला गया।

- कार्यक्रम के दौरान, C-DOT ने अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया, जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के लिए स्वदेशी 4G कोर का विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित समाधान और उन्नत प्रणालियां शामिल हैं, जिन्होंने 5 करोड़ धोखाधड़ी वाले सिम को सफलतापूर्वक डिस्कनेक्ट किया।

- इन नवाचारों ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने में सी-डॉट के योगदान को प्रदर्शित किया।

Key Points:-

(i) स्थापना दिवस पर 6G, साइबर सुरक्षा और क्वांटम संचार अनुसंधान जैसी भविष्य की तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। सी-डॉट ने भारत के दूरसंचार बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और देश को डिजिटल संचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अपने चल रहे अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर प्रकाश डाला।

(ii) इस समारोह के एक भाग के रूप में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित 10 स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय विकास एवं नवाचार दोहन पहल (NIDHI) के अंतर्गत अनुदान प्रदान किया गया। यह पहल नवाचार को बढ़ावा देती है और प्रौद्योगिकी में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करती है।

(iii) इस कार्यक्रम में 1984 में अपनी स्थापना से लेकर भारत के दूरसंचार विकास की रीढ़ बनने तक, सी-डॉट की 41 वर्षों की यात्रा को रेखांकित किया गया। 4G, AI और भविष्य की 6जी तकनीकों में अपनी उपलब्धियों के साथ, सी-डॉट ने नवाचार और डिजिटल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की।

4. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉलेज छात्रों के लिए 'यू-स्पेशल' बस सेवा फिर से शुरू की।



28 अगस्त, 2025 को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉलेज के छात्रों के लिए सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और छात्र-अनुकूल परिवहन प्रदान करने के उद्देश्य से, नई 'U-स्पेशल' बस सेवा का उद्घाटन किया। 25 इलेक्ट्रिक बसों वाली यह सेवा, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और IIT दिल्ली सहित 67 कॉलेजों को 25 मार्गों पर जोड़ती है।

- दिल्ली में कॉलेज के छात्रों की आवागमन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 'U-स्पेशल' बस सेवा फिर से शुरू की गई है। ये 25 इलेक्ट्रिक बसें 25 रूटों पर चलेंगी और दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ेंगी। इन रूटों को कॉलेज के समय के अनुसार डिज़ाइन किया गया है ताकि छात्रों के लिए सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हो सके।

- नई शुरू की गई बसें एयर-कंडीशनिंग, LED लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम से लैस हैं ताकि छात्रों के आवागमन के दौरान आराम और अनुभव को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों में CCTV कैमरे और पैनिक बटन भी लगे हैं।

- प्रदूषण कम करने और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिल्ली की प्रतिबद्धता के अनुरूप, 'यू-स्पेशल' बसें इलेक्ट्रिक हैं और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दे रही हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम हो और शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार हो।

Key Points:-

(i) यात्रा को और भी सुखद बनाने के लिए, बसों में लाइव रेडियो चैनल हैं जिन्हें छात्र क्यूआर कोड के ज़रिए सुन सकते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म न केवल मनोरंजन

प्रदान करता है, बल्कि महत्वपूर्ण सरकारी संदेशों और सामाजिक अभियानों का भी प्रसार करता है, जिससे छात्र अपनी यात्रा के दौरान सूचित और व्यस्त रहते हैं।

(ii) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा और बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उद्घाटन के दौरान, उन्होंने सोशल सेंटर स्कूल को 21 कक्षाओं वाले एक आधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक में बदलने पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक मेंटरशिप कार्यक्रम का भी प्रस्ताव रखा, जिसके तहत विश्वविद्यालय के छात्र आस-पास के सरकारी स्कूलों में जाकर स्कूली बच्चों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देंगे, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को अभिभावकों की पहली पसंद बनाना है।

(iii) सरकार छात्रों की मांग और व्यस्त समय की ज़रूरतों को देखते हुए 'यू-स्पेशल' बसों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाने की योजना बना रही है। इस विस्तार से यह सुनिश्चित होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन विकल्पों तक पहुँच मिले, जिससे सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली में एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण बनाने में योगदान मिलेगा।

INTERNATIONAL

1. फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।



फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 24 से 26 अगस्त, 2025 तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। इस तीन दिवसीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था।

- फिजी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री राबुका ने किया, उनके साथ उनकी पत्नी सुलुती राबुका और वरिष्ठ मंत्रीगण, जिनमें फिजी के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा मंत्री रातू एंटोनियो लालबालावु तथा अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारी शामिल थे।

- इस यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, शिक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार और क्षमता निर्माण पहल जैसे क्षेत्रों में भारत-फिजी सहयोग को बढ़ाना था।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें 'आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता' के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की गई और दोनों देशों के बीच रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई।

Key Points:-

(i) कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रक्षा, गतिशीलता

और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 9 समझौता ज्ञापन (MoUs) और द्विपक्षीय समझौतों का आदान-प्रदान किया गया, जो भारत-फिजी संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(ii) अपनी भारत यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री राबुका ने नई दिल्ली में भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) द्वारा आयोजित 54वें सप्रू हाउस व्याख्यान भी दिया, जहां उन्होंने प्रशांत क्षेत्र के लिए 'शांति के महासागर' के अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया।

(iii) राबुका द्वारा रेखांकित 'शांति के महासागर' की अवधारणा ने प्रशांत देशों के लिए एक शांतिपूर्ण, स्थिर, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के निर्माण पर जोर दिया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हुई।

BANKING & FINANCE

1. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप-केंद्रित शाखा खोली।



पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने स्टार्टअप इंडिया पहल को मजबूत करने और उभरते व्यवसायों के लिए समर्पित वित्तीय और सलाहकार सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में अपनी पहली स्टार्टअप-केंद्रित शाखा शुरू की है।

● नई स्टार्टअप-केंद्रित शाखा का उद्घाटन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के महानिदेशक अरविंद कुमार और PNB के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अशोक चंद्रा की उपस्थिति में किया गया, जिसमें बैंकिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के बीच सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

● इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए विशिष्ट बैंकिंग उत्पाद, सलाहकार सहायता और सरकारी योजनाओं तक पहुंच सहित अनुरूप वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।

● यह भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया मिशन के अनुरूप है, जो नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

Key Points:-

(i) लॉन्च के दौरान, PNB ने सहयोग को मजबूत करने के लिए STPI के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के तहत, STPI वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए पीएनबी के साथ सहयोग करने हेतु इनक्यूबेटेड, ऑनबोर्डेड या ग्रेजुएटेड स्टार्टअप्स की एक सूची तैयार करेगा और उन्हें सहयोग प्रदान करेगा।

(ii) इस स्टार्टअप-केंद्रित शाखा से स्टार्टअप के लिए वन-स्टॉप समाधान की पेशकश करके, पूंजी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने, व्यापार सलाहकार और सरकार समर्थित योजनाओं से विकास और स्थिरता में तेजी लाने के माध्यम से एक मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

ECONOMY & BUSINESS

1. अर्न्स्ट एंड यंग (EY) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2038 तक क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।



अगस्त 2025 में, अर्न्स्ट एंड यंग (EY) ने EY इकोनॉमी वॉच का अगस्त 2025 संस्करण जारी किया, जिसमें बताया गया कि भारत 2038 तक क्रय शक्ति समता (PPP) के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। ये अनुमान 2028-2030 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विकास अनुमानों पर आधारित हैं।

● EY की रिपोर्ट में कहा गया है कि PPP के लिहाज से भारत की GDP 2030 तक 20.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जिससे यह चीन (42.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। निरंतर गति के साथ, अनुमान है कि भारत 2038 तक PPP के लिहाज से अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और दूसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

● भारत की मजबूत विकास गति का श्रेय मजबूत बुनियादी बातों को दिया जाता है, जैसे कि 2025 में केवल 28.8 वर्ष की औसत आयु वाली युवा जनसांख्यिकी, उच्च घरेलू मांग और दुनिया की दूसरी सबसे ऊँची बचत दर।

- इसके अतिरिक्त, प्रबंधनीय स्तर के अंतर्गत सरकारी ऋण-GDP अनुपात के साथ एक स्थायी राजकोषीय ढांचा दीर्घकालिक संभावनाओं को और मजबूत करता है।

Key Points:-

(i) रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अमेरिका अपनी आर्थिक मज़बूती बनाए हुए है, लेकिन उसे धीमी दीर्घकालिक वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद के 120% से ज़्यादा कर्ज़ का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, जर्मनी और जापान जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ती उम्र की आबादी, ऊँची मध्य आयु और वैश्विक व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता से जूझ रही हैं, जिससे उनकी भविष्य की विकास संभावनाएँ सीमित हो रही हैं।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, 2028-2030 के दौरान भारत की औसत अनुमानित वृद्धि दर 6.5% है, जो इसी अवधि में अमेरिका की 2.1% की वृद्धि दर से काफ़ी अधिक है। यह वृद्धि अंतर 2038 तक वैश्विक PPP रैंकिंग में भारत के दूसरे स्थान पर पहुँचने की क्षमता को मज़बूत करता है।

(iii) EY ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर भारत और अमेरिका दोनों 2030 के बाद भी अपनी अनुमानित विकास दर बनाए रखते हैं, तो भारत अगले दशक में PPP GDP रैंकिंग में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। यह अनुमान 21वीं सदी में वैश्विक आर्थिक विस्तार के एक प्रमुख चालक के रूप में भारत की भूमिका को पुष्ट करता है।

MOUs and Agreement

1. भारत और भूटान ने कृषि सहयोग और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



29 अगस्त, 2025 को, भारत और भूटान ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए थिम्पू में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी और भूटान सरकार के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के सचिव थिनले नामग्याल ने हस्ताक्षर किए। यह पहल सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

- समझौता ज्ञापन में ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के माध्यम से कृषि अनुसंधान और नवाचार, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन, फसल-उपरांत प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला विकास और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा की रूपरेखा दी गई है।

- इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों की कृषि उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाना तथा पारस्परिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है।

Key Points:-

(i) हस्ताक्षर समारोह के बाद, संयुक्त तकनीकी कार्य समूह (JTWG) का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। JTWG को कृषि विपणन, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, बीज क्षेत्र विकास, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग, और क्षमता निर्माण पहल जैसे

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। JTWG की स्थापना, समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को कार्यान्वयन योग्य योजनाओं में बदलने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का प्रतीक है।

(ii) यह समझौता भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करता है, जो ग्रामीण समृद्धि और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने के उनके साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय सहयोग और विकास के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप भी है, और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करता है।

(iii) इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादकता में सुधार, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि और भारत तथा भूटान के बीच आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने सहित महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इस सहयोग के माध्यम से, दोनों देशों का लक्ष्य एक अधिक लचीला और टिकाऊ कृषि परिदृश्य तैयार करना है, जो उनके कृषक समुदायों और व्यापक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की भलाई में योगदान देगा।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. जम्मू और कश्मीर बैंक ने अनुभवी बैंकर एस. कृष्णन को नया गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया।

25 अगस्त, 2025 को एक ऐतिहासिक बोर्ड निर्णय में, जम्मू और कश्मीर बैंक (J&K बैंक) ने शंकरसुब्रमण्यम कृष्णन (एस. कृष्णन) को अपना नया गैर-कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मंजूरी के अधीन है। उनका कार्यकाल 26 मार्च, 2028 तक रहेगा, जो शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अनुभवी नेतृत्व को दर्शाता है।

● श्रीनगर स्थित मुख्यालय वाले J&K बैंक के बोर्ड ने 25 अगस्त, 2025 को एस. कृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उन्हें गैर-कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नामित किया गया है और उनका कार्यकाल 26 मार्च, 2028 तक रहेगा, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनके पहले कार्यकाल के साथ संरेखित है।

● कृष्णन वर्तमान में जेएंडके बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक से नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद उनकी अध्यक्षता आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाएगी।

Key Points:-

(i) बैंकिंग में चालीस साल से ज़्यादा के करियर के साथ, कृष्णन ने 1983 में इंडियन बैंक से शुरुआत की। समय के साथ, उन्होंने कॉर्पोरेट ऋण, जोखिम प्रबंधन और मानव संसाधन (HR) में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रबंध निदेशक और CEO (MD-CEO), और बाद में तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक में प्रमुख नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया।

(ii) वाणिज्य में निपुण स्नातकोत्तर और योग्य लागत लेखाकार, कृष्णन को महत्वपूर्ण परिवर्तन और डिजिटल पहलों का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है।

(iii) उनके नेतृत्व में, पंजाब और सिंध बैंक जैसे संस्थानों ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया, जबकि तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक में उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज



लिस्टिंग और डिजिटल अपग्रेडेशन की सुविधा प्रदान की।

2. पूर्व RBI गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को तीन साल के कार्यकाल के लिए IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया।



भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित रवींद्र पटेल की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत के कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ, उन्हें इस बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन साल का कार्यकाल मिलेगा।

• डॉ. उर्जित पटेल की IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दे दी है और उनका कार्यकाल तीन साल का होगा, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। वह इस पद पर डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन का स्थान लेंगे।

• कार्यकारी निदेशक के रूप में, डॉ. पटेल IMF कार्यकारी बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और वैश्विक आर्थिक रणनीति को प्रभावित करने वाले नीतिगत विचार-विमर्श और निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

• डॉ. पटेल ने सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्हें मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचे को लागू करने और बैंकिंग सुधारों को लागू करने में उनके काम के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

Key Points:-

(i) यह नियुक्ति डॉ. पटेल के लिए उस संस्थान में एक महत्वपूर्ण वापसी है जहाँ से उन्होंने आईएमएफ में अर्थशास्त्री के रूप में अपना करियर शुरू किया था। यह पूर्ण-चक्र प्रगति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, दोनों में उनके व्यापक अनुभव को रेखांकित करती है।

(ii) उनकी नियुक्ति को वैश्विक आर्थिक प्रशासन में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण माना जा रहा है। डॉ. पटेल का अनुभव वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के दौर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नीति-निर्माण में भारत के प्रतिनिधित्व को मज़बूत करता है।

(iii) डॉ. पटेल, डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2025 के आरंभ में IMF प्रोटोकॉल के साथ विवाद और असहमति के कारण कम कर दिया गया था, जिससे यह पद रिक्त हो गया था।

3. आकाश त्रिपाठी को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।



अगस्त 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में आकाश त्रिपाठी की नियुक्ति को मंजूरी दी।

- मध्य प्रदेश कैडर के 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी आकाश त्रिपाठी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी का स्थान लेंगे, जो आरपी गुप्ता के जाने के बाद से SECI का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। संतोष कुमार सारंगी SECI के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे।

- SECI के MD के रूप में आकाश त्रिपाठी के लिए मुख्य कार्य भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार का नेतृत्व करना और 2030 तक भारत के 500 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना होगा। सौर और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा।

- इस नियुक्ति से पहले, आकाश त्रिपाठी विद्युत मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण नीति नियोजन और कार्यान्वयन में योगदान दिया। उनका पूर्व अनुभव

उन्हें SECI की नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) अपने पूरे करियर के दौरान, आकाश त्रिपाठी ने कई प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के CEO और MyGov.in के CEO शामिल हैं।

(ii) ये भूमिकाएँ डिजिटल गवर्नेंस, सेमीकंडक्टर विकास और नागरिक सहभागिता में उनकी विशेषज्ञता को उजागर करती हैं, जो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के SECI के मिशन में मूल्यवर्धन करेगी।

(iii) इस नियुक्ति से भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य को बढ़ाने में SECI की भूमिका को और मज़बूत करने की उम्मीद है, जो सरकार के दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण और स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित होगी।

SPORTS

1. FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर, 2025 तक गोवा में किया जाएगा।



अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ने आधिकारिक तौर पर गोवा, भारत को FIDE विश्व कप 2025 के

लिए मेज़बान शहर के रूप में घोषित किया है, जो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 206 शीर्ष खिलाड़ी 2 मिलियन अमरीकी डालर की पुरस्कार राशि और 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए तीन कालीफाइंग स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

- **FIDE विश्व कप 2025 एक द्विवार्षिक नॉकआउट शतरंज टूर्नामेंट होगा, जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कालीफाइंग इवेंट होगा, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए दावेदार का फैसला करेगा। यह गोवा संस्करण को वैश्विक शतरंज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है।**

- **टूर्नामेंट का प्रारूप आठ राउंड का नॉकआउट होगा, जहाँ प्रत्येक मैच में दो क्लासिकल गेम होंगे, और उसके बाद आवश्यकतानुसार रैपिड, ब्लिट्ज़ या आर्मगेडन में टाई-ब्रेकर होंगे। इससे पूरी चैंपियनशिप में गहन और प्रतिस्पर्धी खेल सुनिश्चित होगा।**

- **भागीदारी में 51-206 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी पहले दौर में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि शीर्ष 50 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्वतः ही दूसरे दौर में प्रवेश कर जाएँगे। यह संरचना 90 से अधिक देशों में संतुलित प्रतिस्पर्धा और व्यापक वैश्विक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।**

Key Points:-

(i) इस आयोजन का महत्व 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे कालीफिकेशन स्थान पाने में निहित है। गोवा में शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अपनी जगह पक्की करेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक शतरंज को बढ़ावा मिलेगा और इस खेल को, विशेष रूप से भारत में, और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

(ii) भारत के कम से कम 21 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिनमें विश्वनाथन आनंद, मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश डोमराजू, प्रज्ञानंद आर, अर्जुन एरिगैसी जैसे दिग्गज और विदित गुजराती, निहाल

सरीन, राजा ऋत्विक् आर और अरविंद चितंबरम जैसे कई अन्य ओलंपियाड सितारे शामिल हैं। यह गोवा की मेज़बानी को भारतीय शतरंज के लिए एक मील का पत्थर बनाता है।

(iii) 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि टूर्नामेंट की प्रतिष्ठा को और बढ़ा देती है, तथा इसे दुनिया भर के सबसे अमीर और सबसे प्रतिस्पर्धी शतरंज टूर्नामेंटों में से एक बना देती है, तथा गोवा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज आयोजनों के लिए एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. **संजय सेठ ने सैन्य चिकित्सा और आघात देखभाल को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में MILMEDICON-2025 का उद्घाटन किया।**



28 अगस्त, 2025 को, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने नई दिल्ली स्थित मानेकशां सेंटर में MILMEDICON-2025 का उद्घाटन किया। चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (सेना) द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सैन्य परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक आघात पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में सैन्य चिकित्सा में नवाचारों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ एकत्रित हुए।

● सम्मेलन में सैन्य नर्सिंग सेवा की शताब्दी भी मनाई गई, जिसमें युद्ध और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

● 28-29 अगस्त, 2025 को आयोजित यह दो दिवसीय सम्मेलन रक्षा मंत्रालय के "सुधार वर्ष" का हिस्सा था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना और सैन्य परिचालन स्थितियों में आघात देखभाल क्षमताओं को बढ़ाना था।

● इस कार्यक्रम में उन्नत युद्ध आघात देखभाल, सैन्य स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण और आपातकालीन और युद्धक्षेत्र चिकित्सा प्रतिक्रिया में नवीन रुझानों पर चर्चा की गई।

Key Points:-

(i) 15 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने पैनल चर्चाओं, पोस्टर प्रस्तुतियों और एक वैज्ञानिक गैलरी प्रदर्शनी में भाग लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी ने सैन्य चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भारतीय सशस्त्र बलों, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य चिकित्सा प्रतिनिधिमंडलों, नागरिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।

(ii) अपने उद्घाटन भाषण में, श्री संजय सेठ ने वैश्विक सहयोग, अत्याधुनिक अनुसंधान और सेवा की विरासत के सम्मान के माध्यम से सैन्य चिकित्सा को आगे बढ़ाने के भारत के दृढ़ संकल्प पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस सम्मेलन को भारतीय सैनिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि और भविष्य के लिए तैयार स्वास्थ्य सेवा समाधानों की दिशा में एक कदम बताया।

(iii) MILMEDICON-2025 सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और वैश्विक ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सैन्य कर्मियों की तैयारी और लचीलेपन को बढ़ाना था, और आघात देखभाल

और चिकित्सा नवाचार पर केंद्रित था।

App and Web Portal

1. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ-अल-औलाद संपत्तियों से विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए रखरखाव सहायता प्रदान करने के लिए UMEED पोर्टल मॉड्यूल लॉन्च किया।



27 अगस्त, 2025 को, भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (UMEED) पोर्टल पर एक समर्पित मॉड्यूल पेश किया। यह पहल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप, वक्फ-अल-औलाद संपत्तियों से भरण-पोषण सहायता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है।

● UMEED पोर्टल एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के तहत संचालित होता है और एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 द्वारा शासित होता है। ये नियम पात्र व्यक्तियों को पहचान और निवास का प्रमाण प्रदान करके निष्क्रिय पारिवारिक वक्फ (वक्फ-अलल-औलाद) से रखरखाव के लिए आवेदन करने की अनुमति देते

हैं, जिसमें भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित होते हैं।

- नया लॉन्च किया गया मॉड्यूल लाभार्थियों के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सुरक्षित और सटीक पहचान सुनिश्चित होती है। आवेदन और अनुमोदन प्रक्रियाएँ संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वक्फ बोर्डों द्वारा ऑनलाइन प्रबंधित की जाती हैं, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है और प्रशासनिक देरी कम होती है।

- रखरखाव सहायता का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए, UMEED पोर्टल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का उपयोग करता है। इस प्रणाली के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे बिचौलियों की संख्या कम होती है और जवाबदेही बढ़ती है।

Key Points:-

(i) इस पहल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से प्राप्त वित्तीय सहायता प्रदान करके समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों का उत्थान करना है। आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर, मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों के धर्मार्थ उद्देश्य प्रभावी और समान रूप से पूरे हों।

(ii) 6 जून, 2025 को UMEED पोर्टल के शुभारंभ के बाद से, मंत्रालय इस प्लेटफॉर्म के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। शासनादेश के अनुसार, भारत भर में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है।

(iii) इस मॉड्यूल की शुरुआत भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी बढ़ाकर, उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में

सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने इच्छित धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करें।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र ने झीलों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 27 अगस्त को 'विश्व झील दिवस' घोषित किया।



दिसंबर 2024 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया—A/RES/79/142—जिसके तहत 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। पहला आधिकारिक दिवस 2025 में मनाया गया, जिसका उद्देश्य झीलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण एवं सतत प्रबंधन के लिए वैश्विक कार्रवाई को गति देना है।

- पहला विश्व झील दिवस 27 अगस्त 2025 को मनाया गया, जो झीलों की महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता का प्रतीक है। यह तिथि 27 अगस्त 1984 को जापान के शिगा प्रान्त में आयोजित पहले विश्व झील सम्मेलन के साथ मेल खाती है, जहाँ देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बिवा झील स्थित है।

- यह पहल 2023 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित की गई थी और बाद में इसे इंडोनेशिया के नेतृत्व वाली 50 से ज़्यादा सरकारों के

समर्थन से महासभा में पेश किया गया। यह प्रस्ताव प्रदूषण, अति-उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण झीलों के क्षरण को रोकने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

Key Points:-

(i) विश्व झील दिवस का उद्देश्य झीलों के पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य—जिसमें ताज़ा पानी, जैव विविधता, बाढ़ नियंत्रण, कार्बन भंडारण और मनोरंजन शामिल हैं—के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। यह जल-संबंधी पारिस्थितिक तंत्रों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने में उनकी भूमिका पर भी ज़ोर देता है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र को शैक्षिक और संरक्षण गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) को इस आयोजन को सुगम बनाने का दायित्व सौंपा गया है।

(iii) झीलों दुनिया के सतही मीठे पानी का 90% से ज़्यादा हिस्सा रखती हैं और मानव जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हालाँकि, इन्हें प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, जलवायु-जनित वाष्पीकरण और सुपोषण के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। समन्वित कार्रवाई के बिना, झीलों के पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति में भारी गिरावट आ सकती है।

2. 29 अगस्त 2025 को परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।



29 अगस्त 2025 को, विश्व परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक दिवस है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त विश्व की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है।

● संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 2009 को प्रस्ताव 64/35 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस की स्थापना की थी। 29 अगस्त, 1991 को कज़ाकिस्तान में सेमिपालाटिस्क परमाणु परीक्षण स्थल के बंद होने के सम्मान में 29 अगस्त की तारीख चुनी गई थी।

● यह स्थल विश्व के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थलों में से एक था, जहां 1949 से 1989 के बीच 450 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए, जिससे स्थानीय आबादी के लिए गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुईं।

● 29 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिवस परमाणु परीक्षणों के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। यह आगे परमाणु हथियारों के परीक्षणों में होने वाले विस्फोटों को रोकने और परमाणु-हथियार-मुक्त विश्व के निर्माण के लिए परमाणु परीक्षणों की समाप्ति को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह दिवस परमाणु हथियारों से उत्पन्न चुनौतियों से

निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।

Key Points:-

- (i) हर साल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस पर दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। इनमें शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक चर्चाएँ और मीडिया अभियान शामिल हैं जिनका उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों के प्रभावों और उन्हें रोकने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- (ii) 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) की स्थापना के बावजूद, जिसका उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है, सभी आवश्यक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अभाव के कारण यह संधि अभी तक लागू नहीं हो पाई है।
- (iii) परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभी राष्ट्रों से CTBT पर हस्ताक्षर करने और उसका अनुसमर्थन करने, परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को कायम रखने तथा परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लिए मिलकर काम करने का आह्वान करता है।

3. भारत 2025 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया।



29 अगस्त, 2025 को भारत हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाएगा। यह दिन खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत नागरिकों को प्रतिदिन कम से कम एक घंटा शारीरिक गतिविधि के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

● राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार 2012 में मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया गया था, जिनका जन्म 29 अगस्त, 1905 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। भारतीय हॉकी में अपने असाधारण कौशल और योगदान के लिए प्रसिद्ध, ध्यानचंद की विरासत आज भी देश भर के एथलीटों को प्रेरित करती है।

● यह दिन मेजर ध्यानचंद की हॉकी में अद्वितीय उपलब्धियों, जिनमें तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक शामिल हैं, को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में खेलों और शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

Key Points:-

- (i) पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें खेल प्रतियोगिताएँ, फिटनेस चुनौतियाँ और जागरूकता अभियान शामिल हैं। उदाहरण के लिए, पटना में तीन दिवसीय खेल उत्सव में दौड़, योग, क्विज़ और पारंपरिक खेलों जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनका समापन शहर भर में साइकिल रैली के साथ होता है।
- (ii) युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 29 से 31 अगस्त तक 'एक घंटा, खेल के मैदान में' थीम के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन शुरू किया है।
- (iii) यह पहल नागरिकों को प्रतिदिन कम से कम एक घंटा शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित

करती है, जिससे पूरे देश में स्वस्थ और अधिक सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा मिलता है।

DEFENCE

1. भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरि और INS हिमगिरि को शामिल किया।



भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश) के विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान (ENC) में दो अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट, INS उदयगिरि (यार्ड 12652) और INS हिमगिरि (Yard 3022) को नौसेना में शामिल किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जो अलग-अलग शिपयार्ड में निर्मित दो युद्धपोतों का पहली बार एक साथ जलावतरण था।

- INS उदयगिरि और INS हिमगिरि का जलावतरण भारत के नौसैनिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह पहला ऐसा अवसर है जब दो अलग-अलग शिपयार्डों से एक साथ दो उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट नौसेना में शामिल किए गए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत युद्धपोत निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।

- दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A (शिवालिक-क्लास) फ्रिगेट्स का हिस्सा हैं, जो नौसेना की परिचालन पहुँच को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए स्टील्थ-

गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक उन्नत श्रृंखला है। प्रोजेक्ट 17A, बेहतर स्टील्थ सुविधाओं, स्वचालन और हथियार प्रणालियों के साथ, प्रोजेक्ट 17 की सफलता का अनुसरण करता है।

- नव-नियुक्त जहाजों का नाम आईएनएस उदयगिरि (F35) के पुराने संस्करणों के नाम पर रखा गया है, जो 1976 से 2007 तक सेवा में था, और INS हिमगिरि (F34) जो 1974 से 2005 तक सेवा में था। इन नामों का पुनरुद्धार नौसेना विरासत और परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है।

Key Points:-

(i) INS उदयगिरि का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई में किया गया था और यह MDL द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा जहाज है। दूसरी ओर, INS हिमगिरि का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा किया गया था और यह GRSE द्वारा प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का तीसरा जहाज है।

(ii) दोनों फ्रिगेट भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा स्वयं डिज़ाइन किए गए हैं। ये WDB द्वारा विकसित 100वें और 101वें युद्धपोत हैं, जो भारत में स्वदेशी युद्धपोत डिज़ाइन और विकास क्षमताओं के 50 वर्षों को दर्शाते हैं।

(iii) ये स्टील्थ फ्रिगेट उन्नत हथियारों और सेंसरों से लैस हैं, जो इन्हें नौसेना के सबसे उन्नत प्लेटफार्मों में से एक बनाते हैं। पूर्वी नौसेना बेड़े में शामिल होने पर, ये हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे, जिससे समुद्री मार्गों और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. इज़राइल की एल्बिट सिस्टम्स ने स्पेसएक्स फाल्कन 9 के माध्यम से NAOS सैटेलाइट पर उन्नत JUPITER स्पेस कैमरा लॉन्च किया



अगस्त 2025 में, इज़राइल की रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम्स लिमिटेड (Elbit Systems Limited) ने अपना उन्नत JUPITER स्पेस कैमरा सफलतापूर्वक NAOS (नेशनल एडवांस्ड ऑप्टिकल सिस्टम) सैटेलाइट पर लॉन्च किया। यह प्रक्षेपण वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, कैलिफोर्निया, USA से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा किया गया। यह उपलब्धि पृथ्वी अवलोकन (Earth Observation) के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन, मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग को सशक्त बनाएगी, जिसका उपयोग सैन्य, पर्यावरणीय और वैज्ञानिक कार्यों में होगा।

● NAOS सैटेलाइट को OHB Italia S.p.A. (इटली) ने निर्मित किया है और यह लक्समबर्ग के LUXEOSys (Luxembourg Earth Observation System) कार्यक्रम का हिस्सा है।

● इसे दोहरी उपयोग (सरकारी और सैन्य) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 450 किलोमीटर सन-सिंक्रोनस कक्षा (orbit) में संचालित होता है और इसकी योजना बनाई गई मिशन आयु सात वर्ष है।

● JUPITER कैमरा, एल्बिट सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है, जो इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट

एक्विज़िशन एंड रिकोनाइसेंस (ISTAR) और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) में अपनी विशेषज्ञता को शामिल करता है। इसे विश्व के सबसे उन्नत अंतरिक्ष-आधारित ऑप्टिकल कैमरों में से एक माना जाता है, जो पृथ्वी अवलोकन तकनीक में अद्वितीय सटीकता प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) इमेजिंग डिज़ाइन की दृष्टि से, इस कैमरे में बड़े अपरचर, हल्का ढांचा, और निरंतर लंबी छवि कैप्चर की क्षमता है, जिससे बड़े क्षेत्रों को कुशलता से कवर किया जा सकता है। इसकी मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग क्षमताओं में शामिल हैं: पैन्क्रोमैटिक (उच्च-रिज़ॉल्यूशन ब्लैक-एंड-व्हाइट इमेजिंग), RGB (रेड, ग्रीन, ब्लू टू-कलर इमेजिंग), और नियर-इन्फ्रारेड (NIR चैनल) जो वनस्पति स्वास्थ्य, जल सामग्री और भौतिक गुणों का विश्लेषण करता है।

(ii) यह प्रणाली AI-आधारित इमेज प्रोसेसिंग को समर्थन देती है और इसे ग्राउंड स्टेशन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग रक्षा, नागरिक और अनुसंधान अनुप्रयोगों में होगा। एल्बिट सिस्टम्स ने स्वचालित चेंज डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और मल्टीस्पेक्ट्रल इमेज फ्यूजन के लिए विशेष एल्गोरिद्म भी विकसित किए हैं, जिससे सटीक स्थितिजन्य जागरूकता प्राप्त की जा सके।

(iii) वैश्विक स्तर पर, NAOS-JUPITER का एकीकरण नागरिक, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा। इसके अनुप्रयोगों में सीमा निगरानी, हथियार संधि सत्यापन, सैनिक गतिविधि पर निगरानी, आपदा राहत, पर्यावरण संकट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अध्ययन शामिल हैं। यह NATO (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों को भी उच्च-रिज़ॉल्यूशन पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान करेगा।

2. गूगल ने जेमिनी ऐप में उन्नत AI फोटो-एडिटिंग टूल 'नैनो बनाना' लॉन्च किया।



अगस्त 2025 में, गूगल ने आधिकारिक तौर पर नैनो बनाना का अनावरण किया, जो एक शक्तिशाली नया AI-समर्थित फोटो संपादन फ्रीचर है जिसे उसके जेमिनी ऐप (जिसे जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज भी कहा जाता है) में एकीकृत किया गया है। मुफ्त और प्रीमियम दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध, नैनो बनाना लोगों, पालतू जानवरों और वस्तुओं की पहचान को सुरक्षित रखते हुए यथार्थवादी, बहु-चरणीय छवि संपादन प्रदान करता है।

● गूगल ने पुष्टि की है कि वायरल नैनो बनाना टूल जेमिनी ऐप का हिस्सा है, जो वेब और मोबाइल दोनों पर मुफ्त और सशुल्क उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, जिससे ऐप की दृश्य संपादन क्षमताएं बढ़ जाती हैं।

Key Points:-

(i) नैनो बनाना संपादनों में एकरूपता बनाए रखने की अपनी उत्कृष्ट क्षमता के लिए जाना जाता है—यह सुनिश्चित करता है कि शैली, सेटिंग या रूप-रंग में बदलाव के बावजूद लोग, पालतू जानवर और वस्तुएँ एकरूपता बनाए रखें। यह मल्टी-टर्न एडिटिंग, सीमलेस इमेज ब्लेंडिंग और स्टाइल मिक्सिंग फंक्शन्स को भी सपोर्ट करता है।

(ii) उन्नत डीपमाइंड तकनीकों का लाभ उठाते हुए,

नैनो बनाना मूल छवि संदर्भ या विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाए बिना सटीक, पुनरावृत्त दृश्य और विषय संशोधनों की अनुमति देता है। इसमें स्टाइल मिक्सिंग, स्तरित दृश्य परिवर्तन और अत्यधिक यथार्थवादी रूपांतरण जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।

(iii) हालांकि यह उपकरण छवि संपादन तकनीक में एक बड़ी छलांग है, लेकिन इसके संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, विशेष रूप से डीपफेक और भ्रामक सामग्री तैयार करने में - ये मुद्दे केवल गूगल के लिए ही नहीं हैं, बल्कि जनरेटिव एआई विकास में महत्वपूर्ण हैं।

Static GK

C-DOT	निदेशक: डॉ. पंकज कुमार दलेला	मुख्यालय: नई दिल्ली
Fiji	प्रधान मंत्री: सितिवनी लिगामामादा राबुका	राजधानी : सुवा
Jammu & Kashmir Bank	गैर-कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष: शंकरसुब्रमण्यम कृष्णन (एस. कृष्णन)	मुख्यालय: श्रीनगर
International Monetary Fund (IMF)	प्रबंध निदेशक (MD): क्रिस्टालिना जॉर्जीवा	मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
Indian Navy (IN)	नौसेना प्रमुख (CONS) : एडमिरल दिनेश कुमार (DK) त्रिपाठी	मुख्यालय: नई दिल्ली
SpaceX	CEO : एलोन मस्क	मुख्यालय: हॉथोर्न, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
Goa	मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत	राज्यपाल: अशोक

		गजपति राजू
Bhutan	राजधानी: थिम्पू	आधिकारिक भाषा: ज़ोंगखा